

(ग) बिछिया योजना का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है जिससे डम परियोजना को जल उपलब्ध होगा तथा यह नर्मदा बेसिन के कुल जल ग्रहण क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) से (ग). बिछिया ताल परियोजना 29 अक्टूबर, 1968 को प्राप्त हुई। परियोजना की तकनीकी जांच पूरी की जा चुकी है। यद्यपि बिछिया ताल परियोजना का कमान क्षेत्र 7.5 वर्गमील का एक बहुत ही छोटा बाह क्षेत्र है, तथापि जब तक नर्मदा जल विवाद एक न्यायिकरण द्वारा न्याय निर्णयाधीन है, तब तक भारत सरकार नर्मदा बेसिन (38000 वर्गमील) में किसी भी राज्य में किन्हीं नई परियोजनाओं को चाहे वे बृहद हों या मध्यम, कार्यान्वयन के उपयुक्त नहीं समझती।

मध्य प्रदेश में मण्डला जिले में उपलब्ध सिंचाई के संसाधन

3192. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आबिवासी जिला मण्डला (मध्य प्रदेश) में इस समय सिंचाई के कौन से समाधन उपलब्ध हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 9567 एकड़ शक्यता की 34 सिंचाई स्कीमें पूर्ण हो गई हैं और 7190 एकड़ शक्यता की 3 स्कीमें निर्माणाधीन हैं।

बोधघाट परियोजना प्रतिवेदन

3193. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से बोधघाट परियोजना का परियोजना प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और इसकी तकनीकी जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) बोधघाट परियोजना की विद्युत् उत्पादन क्षमता तथा अन्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) बोधघाट पर परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को अगस्त, 1970 में प्राप्त हुई थी। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत् परियोजनाओं की सलाहकार समिति ने मई, 1971 में हुई अपनी बैठक में स्कीम पर विचार किया और तकनीकी दृष्टि से इसे व्यवहार्य पाया। बहरहाल, इसमें अन्तर-राज्यिक हित निहित थे, इसलिए परियोजना को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार करने से पहले उड़ीसा सरकार में सलाह-मशविरा करना आवश्यक समझा गया।

(ख) इस परियोजना से इन्द्रावती नदी के पानी का समुपयोजन होगा और लगभग 700 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत्-जनन के लिए लगभग 110 मीटर के शीष का समुपयोजन करते हुए परियोजना में 80-80 मेगावाट के तीन विद्युत्-जनन सेटों का प्रतिष्ठापन सम्मिलित है।

Recommendations of Monopolies Commission regarding Export Targets

3194. SHRI SHRIKISHAN MODI : Will the Minister of FOREIGN TRADE be pleased to state :

(a) whether the Monopolies Commission has advised the Centre to fix the export targets of the Undertakings seeking industrial licences on a realistic basis; and

(b) whether Government have accepted the advice ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : (a) Yes, Sir. The Monopolies Commission in their Report dated 25.2.1972 in the case of M/s. Vidut Metalics Ltd. Calcutta, has *inter alia*, suggested that the Government should fix the percentage of export at a level which could be achieved in practice.

(b) The Report is under consideration of the Government in the Department of Company Affairs.

**नर्मदा नदी पर बर्गी बांध का
परियोजना प्रतिवेदन**

3195. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा नदी पर बर्गी बांध का परियोजना प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ तथा क्या तकनीकी परामर्शदात्री समिति द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपसत्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख). बर्गी की परियोजना रिपोर्ट 22 फरवरी, 1969 को प्राप्त हुई थी। तकनीकी सलाहकार समिति ने 6 सितम्बर, 1969 को इस परियोजना पर विचार किया और इसे इस शर्त के अधीन स्वीकार्य माना कि केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और मंत्रालय की टिप्पणियों का पालन किया गया हो। राज्य सरकार ने यह भी कर लिया है।

बहरहाल, इस परियोजना को मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं में सम्मिलित करने के लिए स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि गुजरात सरकार ने इस पर आपत्ति उठायी है और नर्मदा जल-विवाद न्याय निर्णयाधीन है।

**Import of Power Plant for Uttar
Pradesh**

3196. SHRI NARENDRA SINGH BISHT : Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) whether Government of Uttar Pradesh have approached the Central Government with a proposal that a power plant of at least 400 mgw. costing Rs. 60 crores

may be imported and immediately installed on a 'turn key' basis to rescue the State from power famine that would overtake it in 1973-74; and

(b) if so, the Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI B. N. KUREEL) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal is under examination in consultation with the Uttar Pradesh Government.

**Declaration of "Protected Workman"
in Railways**

3197. SHRI PRAVINSINH SOLANKI:
SHRI CHANDRIKA PRASAD :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the Registered Unions Associations on each Railway Zone who have so far applied to the administration for recognition of their office-bearers as "Protected Workman";

(b) the names of the Office bearers, Zone-wise, who have been declared as "Protected Workman";

(c) the names of the Registered Trade Unions/Associations whose applications are still pending with the Administration; and

(d) when their applications are likely to be finalised ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

**Recognition of category-wise Unions
Associations of Railway Employees**

3198. SHRI PRAVINSINH SOLANKI :
SHRI CHANDRIKA PRASAD :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :